

# 1 कार्यकारी सारांश

## 1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत भारत में फ्राइट के बेहतर संचरण करने के लिए इकनोमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट्स एवं नेशनल कॉरिडोर प्रस्तावित किया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तावित दुर्ग रायपुर सेक्शन का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो कि [राष्ट्रीय राजमार्ग 53]- मुंबई कोलकाता इकनोमिक कॉरिडोर [लॉट 3 / पैकेज -1] का एक हिस्सा है।

## 1.2 परियोजना का विवरण

परियोजना डिजाइन चैनेज 0+000 कि०मी० से शुरू होती है, और डिजाइन चैनेज 92+230 कि०मी० पर समाप्त होता है [मौजूदा चैनेज 329+400 कि०मी० टेंडेसारा के पास से 229+730 कि०मी० अरांग के पास तक]।

यह मुंबई कोलकाता इकनोमिक कॉरिडोर [लॉट 3 / पैकेज -1] का एक हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 92.200 कि०मी० है।

प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ के तीन जिलों 'राजनंदगांव, दुर्ग और रायपुर' से गुजरती है। परियोजना राजनंदगांव, दुर्ग, पाटन, अभनपुर और अरांग तहसील से गुजरती हैं।

प्रस्तावित परियोजना का राइट ऑफ वे (आर०ओ०डब्ल्यू) 70 मीटर है।

प्रस्तावित सड़क किसी वन क्षेत्र या वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र से नहीं गुजर रही है।

परियोजना के लिए करीब 746.614 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। अध्ययन क्षेत्र में लैंडयूज पैटर्न मुख्य रूप से कृषि है, इसके बाद बस्तियां और बंजर भूमि है।

स्थानीय लोगों, जानवरों के लिए सहज आवागमन हेतु और स्थानीय जल स्रोतों के निकास पर किसी भी प्रभाव से बचने के लिए परियोजना में 39 वीयूपी, 2 आरओबी, 4 आरयूबी, 6 प्रमुख पुल, 27 छोटे पुल और 167 कल्वर्ट प्रस्तावित किए गए हैं।

निर्माण के दौरान निर्माण के लिए पानी की कुल आवश्यकता लगभग 2972249 KL अपेक्षित की गयी है, जो टैंकर आपूर्ति या भूजल (यदि आवश्यक हो) से व्यवस्थित की जाएगी।

निर्माण की समाप्ति अवधि लगभग 36 महीने होने का अनुमान है। अनुमानित लागत लगभग 1383 करोड़ रुपये है।

### 1.3 पर्यावरण का विवरण

बेसलाइन डेटा प्री मानसून सीजन के दौरान मार्च से मई, 2018 के दौरान एकत्र किया गया था। बेसलाइन डेटा ई आई ए रिपोर्ट के अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है जो दिखाता है कि लगभग सभी मानकों के मूल्य निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

### 1.4 अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन के उपाय

- हीट आइलैंड प्रभाव के कारण क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु में थोड़ा बदलाव होने की अपेक्षा है।
- निर्माण गतिविधियों के दौरान पीएम के स्तर में मामूली वृद्धि होगी, जो निर्माण गतिविधियों खत्म होने के बाद फिर से निर्धारित सीमा के भीतर हो जाएगी।
- सड़क के निर्माण के बाद ट्रैफिक डेंसिटी में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में शोर स्तर में मामूली वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है।
- निर्माण सामग्री, तेल, तेल, ईंधन और पेंट इत्यादि के फैलाव के कारण जल निकायों के लिए प्रदूषण हो सकता है। यह उन स्थलों में अधिक प्रमुख होगा जहां परियोजना सड़क, नदियां, नहरों, नाला आदि को पार करती है। इसके लिए शमन के उपाय बनाये गये हैं जो के इन जल निकायों को प्रदूषण से बचायेंगी।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान, परियोजनाओं के निर्माण के कारण स्थलाकृति मामूली रूप से बदल सकती है।

### 1.5 विकल्प का विश्लेषण

विकल्पों का विस्तृत विश्लेषण आयोजित किया गया है। सभी विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण भी आयोजित किया गया है। सड़क के प्रस्तावित विकास से क्षेत्र के आर्थिक मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, कुछ पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें सतत विकास के लिए कम करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित परियोजना के लिए तीन विकल्पों का अध्ययन किया गया था जिनमें से प्रस्तावित राजमार्ग सबसे उपयुक्त पाया गया।

### 1.6 पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रोग्राम

प्रस्तावित परियोजना के संचालन के दौरान पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मानकों की नियमित निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधारभूत स्थितियों की जानकारी,

परियोजना के संचालन के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी भी गिरावट के संकेतक के रूप में कार्य कर सकती है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय पर उपयुक्त कमजोर कदम उठाए जा सकते हैं। निगरानी एवं शमन के उपाय प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता केवल निगरानी द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गयी है।

### 1.7 परियोजना के लाभ

परियोजना के लाभ बहु गुना हैं। यह बिलासपुर और कोरबा एवं अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगा। बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा, यह समर्पित परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों / कस्बों की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देगा।

### 1.8 परियोजना के लाभ

### 1.9 पर्यावरण प्रबंधन योजना

प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना प्रभाव और प्रबंधन योजना का सारांश दिया गया है।

पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाइन किया गया है:

- वनस्पतियों और जीवों में अशांति को कम करने हेतु।
- वायु, जल, मिट्टी और शोर प्रदूषण को रोकने एवं कम करने हेतु।
- सामाजिक-आर्थिक विकास में बेहतरी हेतु।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल होंगे:

- संभावित प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक), पर्यावरणीय शमन उपायों, कार्यान्वयन अनुसूची, और निगरानी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए।
- परियोजना विकास के प्रत्येक चरण से जुड़े संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और प्रस्तावित प्रबंधन का वर्णन करने के लिए।

- स्वीकार्य मानकों के स्तर के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए, निर्माण के दौरान समुदाय के संभावित प्रभाव को कम करने और परियोजना के बाद के परिचालन चरणों के दौरान संभावित जोखिमों के कार्यबल को कम करने के लिए।

### 1.10 निष्कर्ष

ईआईए अध्ययन और परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईआईए रिपोर्ट में बताए गए उपायों के पर्याप्त कार्यान्वयन से संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को स्वीकार्य स्तर पर कम किया जा सकता है।

पर्यावरणीय बजट में सुझाए गए पर्यावरणीय शमन उपायों, और उनके संबंधित लागत को कवर करने के लिए परियोजना में पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे।

प्रस्तावित परियोजना सड़क दक्षता में सुधार करेगी और आर्थिक विकास लाएगी।